

has completed the examination of the report and given its recommendations thereon.

Share of Amount Spent on Sardar Sarovar (Narmada) Project

644. SHRI R. P. GAEKWAD: Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that none of the participating States in the construction of Sardar Sarovar (Narmada) Project has yet paid its share of the expenditure incurred upto 31st March, 1982;

(b) if so, what is the share of each of the participating States upto March 1982;

(c) whether it is correct that Gujarat alone has so far borne the entire financial burden on this massive project; and

(d) if so, steps taken or proposed to be taken to persuade these States to pay their contributions in time?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI Z. R. ANSARI): (a) to (d). The Government of Gujarat who have been executing the Sardar Sarovar Project, have intimated that an expenditure of Rs. 128.80 crores is anticipated to have been incurred by them on the project upto March, 1982. The share cost of the participating States is as under:—

1. Gujarat	Rs. 75.51	crores
2. Maharashtra	Rs. 15.40	crores
3. Madhya Pradesh	Rs. 32.51	crores
4. Rajasthan	Rs. 5.38	crores
<hr/>		
Total	Rs. 128.80	crores

The matter in regard to payment of their share cost of expenditure by the other three participating States of Maharashtra, Madhya Pradesh and Rajasthan has already been taken up actively by the Centre with these State Governments and they have been requested

that the arrears should be paid in three instalments commencing from 1982-83. This matter is being further pursued.

External assistance for Sardar Sarovar (Narmada) Project

645. SHRI R. P. GAEKWAD : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government are exploring the possibilities of obtaining external assistance from sources other than the World Bank in the expeditious completion of Sardar Sarovar (Narmada) Project;

(b) if so, what are those sources and the quantum of assistance sought for; and

(c) if not, reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI Z. R. ANSARI): (a). No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The project is at present under discussion stage for assistance from the World Bank. As such the Question of obtaining external assistance from sources other than World Bank does not arise.

Fall in raw cashew price

646. SHR K. A. SWAMI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the reasons for the sudden steep fall in the price of raw cashew;

(b) whether it is a fact that the price of the finished cashew product has continued to increase;

(c) the reasons for this anomalous situation; and

(d) the steps taken to assure the cashew farmers a better price?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a). The price of raw cashew has declined as a result of

decline in international price, sluggish exports, loss lifting by processors-cum-exporters from Kerala State Co-operative Marketing Federation.

(b) and (c). No, Sir. The wholesale prices of cashewnut have shown a declining trend in recent months.

(d) The Government of Kerala under the scheme of monopoly procurement of raw cashewnut procures raw cashewnut through the agency of Kerala State Co-operative Marketing Federation at prices fixed by the State Government. The Government of Kerala is trying to negotiate with the processors-cum-exporters for more lifting from the Kerala State Co-operative Marketing Federation.

गया, नावादा और नालन्दा जिलों के गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना

647. श्री कुंवर राम : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन पर गया, नावादा और नालन्दा जिलों के गांवों को ग्रामीण विकास विभाग की सहायता से सड़कों से जोड़ने का काम चल रहा है ;

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाओं का काम वर्ष 1983-84 तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(ग) इन जिलों के कितने गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की संभावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग). न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी मौसमों में खली रहने वाली सड़कों से गांवों को जोड़ने के लिए बिहार सहित राज्यों को सहायता सुलभ करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय में कोई योजना नहीं है। ग्रामीण सड़क कार्यक्रम जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का भाग है, राज्य क्षेत्रों में है तथा इसके लिए राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों की योजनाओं में व्यवस्था की जाती है।

बिहार में छोटे शहर विकास परियोजना

648. श्री कुंवर राम : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे शहर विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत बिहार नालन्दा, बिहार शरीफ, राजगढ़ नावादा और राजौली के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि मंजूर की गई है और कितने समय के लिए; और

(ख) उसमें राज्य सरकार के अंशदान का अनुपात कितना है और स्वीकृत परियोजनाओं को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क). उल्लिखित शहरों में से किसी भी शहर को केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी भी योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पिछले दो वर्षों के दौरान बिहार की मंजूर की गई सिंचाई परियोजनाएं

649. श्री कुंवर राम : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान बिहार की कितनी सिंचाई परियोजनाएं मंजूर की ;

(ख) लम्बित परियोजनाओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक परियोजना कब से लम्बित है ;

(ग) मंजूर शुदा परियोजनाओं के लिए चालू वर्ष में कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और

(घ) उक्त धनराशि में से कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जुलाई, 1980 से जून, 1982 तक बिहार की बारह मध्यम सिंचाई स्कीमों अनुमोदित की गईं।